एक नजर में

असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना लागू

धार। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना अंतर्गत असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना लागू की गई हैं। जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के सभी असंगठित कर्मकार (रिक्शा चालक, करीवाला, मजदूर (निर्माण), घरेलू कामगार, दर्जी, पान वाले एवं छोटी दुकान वाले या इसी तरह के अन्य कामगार) पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम हैं, जो कर्मचारी राज्य बीमा अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (पीएफ) में सम्मिलित नहीं हैं एवं आयकर दाता नहीं है। हितग्राही के मासिक अंशदान (न्यूनतम 55 रुपये से अधिकतम 200 रुपये तक) के बराबर अंशदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय, योजना अंतर्गत 60 वर्ष की आयु उपरांत आजीवन निश्चित पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान हितग्राही को प्राप्त होगा।उन्होंने बताया कि आवेदक इस योजना से जु?ने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर में जाकर आधार कार्ड तथा बचत, जन धन खाते के दस्तावेज प्रस्तुत करें।इसमें आवेदक पहली योगदान का भुगतान नगद से करेगा, तत्काल कम्प्यूटर से स्वत: डेबिट अधिदेश उत्पन्न होगा जिस पर आवेदक हस्ताक्षर करेगा, आवेदक को कम्प्यूटर जनित श्रम योगी पेंशन कार्ड तुरंत दिया जावेगा, अगले माह से निर्धारित योगदान का भुगतान आवेदक के बैंक खाते से स्वत: डेबिट होगा।

अभिभाषक पर हुए हमले के विरोध में हड़ताल

सरदारपुर। अभिभाषक वीरेंद्र सिंह राठौर के ऊपर सामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के विरुद्ध एवं शिवपुरी के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए आज अभिभाषक संघ सरदारपुर न्यायालयीन कार्य से विरत रहा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन राज भवन भोपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीम सरदारपुर को अभिभाषक संघ सरदारपुर ने सौंपा इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष कमल किशोर वैष्णव उपाध्यक्ष श्री रामलाल पाटिल सचिव श्री दिलीप सिंह भदोरिया सहायक सचिव श्री ईश्वरलाल पाटीदार श्री मनीष सिसोदिया श्री दिग्विजय सिंह राठौर अनिल यादव अनिल भूरिया श्री भूपेन्द्र जोशी दिलीप सिंह चौहान दीपेश गर्ग अनिल पांडे सचिन बैरागी योगेंद्र उपाध्याय नितिन शर्मा दिनेश जायसवाल अंकित कछावा दिलीप वसुनिया हरिराम मुनिया हेमेंद्र बैरागी आदि अन्य अभिभाषक उपस्थित थे

भाजपा का आजीवन समर्पण निधि एकत्रीकरण अभियान

इंदौर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को भाजपा समर्पण दिवस के रूप में मनाती है, उसी दिन से आजीवन समर्पण निधि अभियान प्रारंभ होता है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संगठन के सशक्तिकरण के लिए धन संग्रहण का अभियान प्रारंभ करते हैं. यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा।इस अभियान के निमित आज भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक व अभियान नगर प्रभारी गोलू शुक्ला, सह प्रभारी हरप्रीत सिंह बक्शी, मुकेश मंगल विभिन्न नेताओं के निवास पहुंचकर आजीवन समर्पण निधि एकत्रीकरण कार्य कर रहे हैं. इसी क्रम में आज भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक व अभियान नगर प्रभारी गोलू शुक्ला, सह प्रभारी हरप्रीत सिंह बक्शी, मुकेश मंगल, मंडल अध्यक्ष नीतेश जैन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निवास पहुंचे, श्रीमती महाजन ने समर्पण निधि का चेक नेताओं को भेंट किया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निवास पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक शुक्ला, सह प्रभारी हरप्रीत सिंह, मुकेश मंगल, निगम सभापति मुन्नालाल यादव, मंडल अध्यक्ष पिंटू चौधरी पहुंचे, उन्होंने मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय से समर्पण निधि का चेक संग्रहित किया. सभी नेताओं ने उन्हें रसीद भेंट की. इसके पश्चात सांसद शंकर लालवानी के निवास पहुंचे वहां श्री लालवानी ने अपनी निधि का चेक नेताओं को दिया. महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निवास पहुंचकर राशि चेक एकत्रीकरण किया.

भोले का किया महाकाल स्वरूप में श्रृंगार

इंदौर. नवरतन बाग स्थित श्री विजय मारुति हनुमान मन्दिर में महंत मंगलदास महाराज खाकी के सानिध्य में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. प्रवीण जोशी ने बताया कि शिवालय में रूद्राभिषेक हुआ। भोलेनाथ को महाकाल के स्वरूप में सुंदर श्रृंगार किया गया. महाआरती के बाद शिवभक्तों में 5 किंवटल फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया. इस मौके पर राधा सुशील उपाध्याय,अर्चना ललित रुईया, रुचि गौरव चोखानी महेश पाल, ललित परदेशी विशेष रूप से उपस्थित थे.

केंद्रीय बजट विशेष कार्यक्रम का आयोजन कल

इंदौर. देश के आगामी आर्थिक परिदृश्य को समझने एवं केंद्रीय बजट 2026-27 के विभिन्न आयामों पर चर्चा हेतु अनलॉकिंग केंद्रीय बजट 2026-27卐 विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 18 फरवरी को दोपहर 12.20 बजे किया जाएगा. यह कार्यक्रम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े विद्वानों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता से आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं के रूप में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहेंगे. सांसद शंकर लालवानी बजट के राष्ट्रीय विकास एवं जनहित से जुड़े पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे. दिनेश बिसेन, अतिरिक्त आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी, इंदौर एवं उज्जैन कर व्यवस्था, जीएसटी सुधार एवं व्यापारिक सुगमता से जुड़े बजट प्रावधानों की जानकारी देंगे. गौतम कोठारी अध्यक्ष पीथमपुर औद्योगिक संगठन उद्योग क्षेत्र पर बजट के प्रभाव, निवेश संभावनाओं एवं रोजगार सृजन के अवसरों पर अपने विचार साझा करेंगे. गौरव गोयल, एम/एस नाइस इंदौर व्यापारिक दृष्टिकोण से बजट के व्यावहारिक प्रभावों पर प्रकाश डालेंगे. कार्यक्रम में विशेष शैक्षणिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए प्रो. पी.एन. मिश्रा, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएवीवी, इंदौर बजट के व्यापक आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे. कार्यक्रम के दौरान बजट के सामाजिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम नीति, उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा.

राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ

गौतमपुरा. देपालपुर विधानसभा के ग्राम पीरनलवासा में बजरंग क्लब द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला संघ अध्यक्ष राधेश्याम जी पटेल सम्मिलित हुए. आयोजकों व खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया प्रतियोगिता का पहला मैच ग्राम कुलाला की टीम(पटेल क्लब) और पीरनलवासा की टीम (बजरंग क्लब)की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व खेल कौशल का प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए, आयोजक क्लब की मांग पर कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम पटेल जी ने कबड्डी मेट देने की महत्वपूर्ण घोषणा की. इस दौरान श्री पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संसाधनों की कमी को दूर करना हमारी प्राथमिकता है, ताकि यहाँ के युवा भी मैट पर अभ्यास कर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार हो सकें. इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व ब्लाक अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन चौधरी, पूर्व सरपंच मांगू सिंह जी ग्राम पंचायत कमेटी अध्यक्ष दरबार सिंह जी वरिष्ठनेता सुंदरलाल जी खटोड,निर्भयसिंह जी सोलंकी,राजपालसिंह सोलंकी व समस्त ग्रामवासी और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

सायबर पंजीयन में पेपरलेस-कैशलेस पहल : सीएम डॉ. यादव

मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पॉवर ऑफ अटार्नी जैसी 75 से अधिक सेवाओं का हो रहा है सायबर पंजीयन

- नवाचार सुशासन के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण
- संपदा 2.0 को मिला है वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ

धार 16 फरवरी, 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जनकल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। पंजीयन विभाग के सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। संपदा-1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में सायबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है। मध्यप्रदेश तेजी से बदल रहा है। मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन, मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर आफ अटार्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी 75 से अधिक सेवाओं के लिए सायबर पंजीयन प्रारंभ किया है। राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद ये विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस

रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पडेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो केवायसी सहित सभी कार्य होंगे, इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संपदा 2.0 के नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अब तक 14 लाख 95 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। राज्य सरकार ने 55 जिलों में सायबर तहसील परियोजना को लागू किया है, जिसमें राजस्व बंटवारा, नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारी सायबर पंजीयन सुविधा के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लक्ष्य पूरे करें।

उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 लागू किया। इससे चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल और पेपरलेस तरीके से पंजीकृत हो रहे हैं। कई दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनके लिए उप-पंजीयक कार्यालय भी नहीं आना प?ता है। सबसे पहले गुना,हरदा, रतलाम और डिण्डौरी जिलों में नए ई-पंजीयन और ई- स्थम्पिंग सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। प्रदेश के नवाचारों को देशभर में सराहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जारी इन नवाचारों का लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिल रहा हैं। पंजीयन से जु? कार्यों को त्रूटि रहित पूरा करने के लिए प्रदेशभर के 14 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री अमित राठौर, प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री अमित तोमर उपस्थित रहे। कार्यक्रम से जिलों के अधिकारी, बैंककर्मी और लाभार्थी वर्चुअली जु?।

जनगणना 2027 प्रथम चरण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

धार, । प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण स्तरीय प्रशिक्षण मंगलवार को कलेक्टर सभागृह में आयोजित किया गया। जिसमें कलेक्टर मिश्रा द्वारा जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। साथ ही सभी जनगणना चार्ज अधिकारियों को जनगणना के डाटा संकलन का महत्व बताया गया। जिसमें शासन स्तर पर जो पूर्व डाटा संकलित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से वास्तवितक स्थिति का आकलंन करने में योजना बनाने में ग्राम से लेकर विकास खण्ड, तहसील और जिला स्तर पर कठिनाई आती है।

प्रशिक्षण में भोपाल से आये प्रशिक्षक श्री सुरज बडगे एवं श्री हुकुमचंद परवते द्वारा जनगणना

कार्यों की बारीकियों की जानकारी विस्तार से दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि जिले में दो चरणों में जनगणना का कार्य होगा। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 के मध्य किया जाएगा। जिसमें मकान का सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जायेगा। वहीं द्वितीय चरण का कार्य फरवरी 2027 में संपन्न होना है। इस बार जनगणना का कार्य डिजिटल रूप से मोबाइल एप के माध्यम से आंकों का संकलन कर किया जायेगा, जो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस बार नागरिकों को अपना जनगणना डेटा स्वयं ऑनलाईन भरने की सुविधा के लिये स्व गणना वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना कार्य से जु महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ-साथ अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी अधिकारियों को दी गई। साथ ही, जनगणना कार्य के दौरान संभावित समस्याओं और प्रश्नों पर प्रतिभागियों से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। भारत की जनगणना, भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बा एकल स्रोत है। भारत की जनगणना को दुनिया के सबसे बे प्रशासनिक कार्यों में से एक माना जाता है। आगामी जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी जो वर्ष 1872 से 16 वीं एवं स्वतंत्रता के बाद की 8 वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। जनगणना 2027 में स्व.गणना पोर्टल, मोबाइल एप के माध्यम से आंकों का संकलन किया जायेगा। इसी क्रम में मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रिएटर वेब पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन किया जायेगा। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली वेब पोर्टल के माध्यम से मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी।इस दौरान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनगणना लिपिक, नगर जनगणना अधिकारी, चार्ज अधिकार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत सुसारी विकासखंड के निसरपुर में शिविर आयोजित

धार. संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत सुसारी विकासखंड के निसरपुर में शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के प्रारंभ में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में उपस्थित नागरिकों को

- कुल 504 आवेदन दर्ज, विभागीय योजनाओं की दी गई विस्तृत जानकारी

विस्तार से अवगत कराया गया।

शिविर के दौरान मौके पर कुल 68 आवेदन प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त क्लस्टर की 16 पंचायतों में पूर्व से दर्ज 436 आवेदन शामिल करते हुए इस प्रकार कुल 504 आवेदन दर्ज किए गए।अभियान के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

शिविर में नोडल अधिकारी श्रीराम बरडे, जिला आपूर्ति अधिकारी; शिविर प्रभारी हीरालाल निगवाल, खंड शिक्षा अधिकारी; मुख्य कार्यपालन अधिकारी, निसरपुर; श्री अनुराग वर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, निसरपुर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित सहित क्लस्टर की 16 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव, सरपंच एवं उपसरपंच उपस्थित रहे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनीं

66 आवेदनों पर हुई सुनवाई, कई का मौके पर निराकरण

धार, 17 फरवरी 2026। प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई के अंतर्गत आज जिला पंचायत धार के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक चौधरी की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों द्वारा कुल 66 आवेदन प्रस्तुत किए गए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी चौधरी ने जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना। इस दौरान कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रेषित करते हुए समय-सीमा में त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में कारम बांध से प्रभावितों को मुआवजा राशि दिलाने, भूखंडों से अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, आर्थिक सहायता प्रदान करने, बिजली गिरने से गायों की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिलाने, आवासीय पट्टा एवं मत्स्यपालन हेतु पट्टा दिलाने, सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा एवं पट्टा दिलाने, आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने, कोटवार के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों से संबंधित समस्याओं के निराकरण से जुड़े आवेदन प्रमुख रूप से शामिल रहे।मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चौधरी ने कहा कि जनसुनवाई शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। प्रत्येक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण प्रशासन की प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर में | **चोरबावड़ी के ग्रामीणों नें तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन**

ग्रामसभा की अनुमति के बिना भूमि आवंटन का विरोध

कुक्षी। समीपस्थ ग्राम लोणी चोरबावड़ी में हस्तशिल्प परियोजना के लिए शासन द्वारा किए गए भूमि आवंटन के विरोध में ग्रामीणों ने लामबंद होकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना किया गया यह आवंटन नियमों के विरुद्ध है और इसे तत्काल निरस्त किया जाए।

ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम लोणी चोरबावड़ी स्थित खसरा नंबर 89 (रकबा 1.310 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 93 (रकबा 1.811 हेक्टेयर) में से 0.300 हेक्टेयर भूमि हस्तशिल्प परियोजना के लिए आवंटित की गई है। इस संबंध में 25 जनवरी को आयोजित ग्रामसभा एवं पेसा

एक्ट समिति की बैठक में सरपंच, समिति अध्यक्ष और समस्त ग्रामीणों ने एकमत होकर इस परियोजना का विरोध किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हस्तशिल्प या अन्य किसी भी परियोजना के लिए ग्रामसभा ने कभी कोई सहमति या अनुमोदन नहीं दिया है.

आंदोलन की दी चेतावनी- ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि हस्तशिल्प परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया, तो क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी।

ज्ञापन का वाचन जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजाल्दा ने किया। इस दौरान समाजसेवी रमेश पाटीदार, सुदामा पाटीदार, प्रकाश मुझाल्दा, हेमंत पाटीदार, देवराम मुझाल्दा, लक्ष्मण भायल, लालसिंह कन्नौज, शंकर जमरा, मनो द्यज जमरा, उमानसिंह पटेल, गेंदालाल राणदा, दीपक पाटीदार, कालू पटेल, संदीप पाटीदार, कन्हैया कन्नौज सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति,कालाबाई जमरा, राधिकाबाई, बबीताबाई, अनिताबाई चौहान, राजकोरबाई, किरणबाई आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।